हिंदी विवेक
WE WORK FOR A BETTER WORLD
Issue : 06 -12 September 2026
संयुक्त अंक

आपदा कहीं मानवीय भूल तो नहीं...

पितांबरी
देवभक्ती
अगरबत्ती
जहाँ श्रद्धा और भक्ति,
वहाँ महके
पितांबरी देवभक्ती!
Agarbatti with
Natural Ingredients
चंदन
गुलाब
मोगरा
Also available in
other fragrances.
Pitambari Products Pvt. Ltd.
Maharashtra: 8291853804, North: 7011012599, South: 9886553105,
East: 7752023380, 9867102999, CRM: 022 - 67035564 / 5699, Toll Free: 18001031299
Visit: www.pitambari.com | CIN: U52291MH1989PTC051314

अनुक्रमणिका

जल-प्रलय की चेतावनी	रंजीत कुमार	04
हिमालय का क्रंदन	पंकज चतुर्वेदी	06
करनी चीन की, भरनी नेपाल की	रामेंद्र सिन्हा	09
सहयोग भारत के डीएनए में	आशुतोष कुमार सिंह	11
जरा मटकी सम्भाल ब्रजबाला	स्निग्धा अवतंस	13
भारत गढ़ेंगा राष्ट्रबोध से	आशीष कुमार 'अंशु'	15
महंगी रसोई डगमगाता आर्थिक संतुलन	सतीश सिंह	17
उगते सूर्य को फिर अस्त करने का षड़्यंत्र	डॉ. अर्पण जैन 'अविचल'	19
साक्षरता से आगे: राष्ट्र साक्षरता	प्रो. अलकेश चतुर्वेदी	21
विश्व कप हॉकी में भारत का स्थान	राजीव रोहित	24
बंटवारा 1947: फिल्म या नैरेटिव का खेल	अतुल गंगवार	26
इधर भी देखें...	संकलन	28
समाचार	-	29

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

पंजीयन शुल्क

वार्षिक मूल्य : 500 रुपये, त्रैवार्षिक मूल्य : 1200 रुपये
पंचवार्षिक मूल्य : 1800 रुपये, आजीवन मूल्य : 25,000 रुपये

कार्यालय : प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067 फोन नं. : 022-28675299, 022-28678933

रंजीत कुमार

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने न केवल पड़ोसी देश को झकझोर दिया, बल्कि भारत की उन दर्दनाक यादों को भी ताजा कर दिया जब केदारनाथ, चमोली और सिक्किम जैसी आपदाओं ने पहाड़ों की नाजुकता उजागर की थी।

नेपाल में गत 26 अगस्त को आयी विनाशकारी प्रलय-बाढ़ ने पिछले दशक के दौरान भारत में आयी ऐसी ही प्राकृतिक आपदाओं की दुखद यादें ताजा कर दीं। 2013 में केदारनाथ, 2021 में उत्तराखंड की चमोली घाटी और 2023 में सिक्किम में आई अचानक बाढ़ ने व्यापक तबाही फैला कर विनाश का तांडव मचाया था। जान-माल का अकल्पनीय नुकसान, तबाही और मौत का वही मंजर नेपाल में देखने को मिला जो हमने केदारनाथ, चमोली और सिक्किम में देखे थे। पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने मानवीय सहायता की। वही जिम्मेदारी सम्भाली जो वह अपने देश के भीतर किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान करने को तत्पर हो जाता है। लेकिन चूंकि यह जिम्मेदारी पड़ोसी सम्प्रभु देश में निभानी थी इसलिए इसकी संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना होता है। फिर भी पड़ोसी सरकार से पूछकर भारत सरकार ने अपनी वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और उन्हें समुचित सहायता तुरंत पहुंचानी शरू कर दी। नेपाल एक छोटा देश है। जिसके पास संसाधन कम हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उसने अपने लोगों के कल्याण और देखभाल के लिए भारत की सहायता का स्वागत किया। भारत सरकार ने पचास टन से अधिक सहायता सामग्री, जिसमें दवाएं, खाद्य सामग्री, रिहायशी

जल-प्रलय की चेतावनी

टेंटस आदि घटनास्थल पर पहुंचा कर वसुधैव कुटुम्बकम की मिसाल एक बार फिर पेश की।

26 अगस्त को भोटकोशी नदी के ऊपर स्थित पहाड़ी पर कई वर्ग किलोमीटर में फैले हिमनदीय मलबे ने आसपास के हजारों लोगों को अपनी गोद में समा लिया। नेपाल-तिब्बत सीमा पर बसे रासुवा क्षेत्र से होकर तिब्बत स्थित कैलाश-मानसरोवर के दर्शन करने वाले सैकड़ों यात्री तो फंसे ही, इस क्षेत्र में स्थित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगें भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। इनमें फँसे सैकड़ों कामगारों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने सुरंग दुर्घटना बचाव की विशेष टीम भी रवाना की। आलेख लिखे जाने तक हजार से भी अधिक लोगों के शव बरामद किए जा चुके थे और हजार से भी अधिक लोगों को बाढ़ के मलवे से सुरक्षित निकाला जा सका था।

नेपाल में इस बार आई अचानक बाढ़ के कई कारण थे। नेपाल-तिब्बत सीमा पर बसे रासुवा गाँव के ऊपर बर्फीली चट्टानी पहाड़ियों (जिन्हें ग्लेशियर या हिमनद भी कहा जा सकता है) ने अपनी धरातल इसलिए छोड़ दी थी कि उस क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों से उत्पन्न कंपन और औसत तापमान बढ़ने से जलवायु में व्यापक परिवर्तन होने लगा। इससे बर्फ से जुड़ी चट्टानें हिमस्खलन (एवलांच) का रूप लेने लगीं। ये विशालकाय बर्फीली चट्टानें लुढ़ककर नीचे भोटकोशी नदी में गिर पड़ीं, जिससे नदी का जलप्रवाह भारी वेग से आगे बढ़ा और उसकी चपेट में हजारों लोग आ गए।

आज के आधुनिक औद्योगिक युग में प्राकृतिक आपदाएं पूर्व सूचना या चेतावनी देकर नहीं आतीं, बल्कि ये अवश्य स्मरण कराती रहती हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाले मानव समुदाय को इसका परिणाम अवश्य भुगतना होगा। सिक्किम, केदारनाथ, चमोली और नेपाल की प्राकृतिक आपदाओं में एक समान बात या कारक यह कहा जा सकता है कि ये सभी विपत्तियां पहाड़ों पर ही अपने सबसे विकराल रूप में दिखीं।

इन सभी प्राकृतिक आपदाओं ने मानव समुदाय को एक बड़ा सबक यह दिया है कि अब भी सम्भल जाएं, अन्यथा भविष्य में विनाश का इससे भी विकराल रूप देखने को मिल सकता है। वैसे तो पर्वतमालाएं प्राचीन काल से ही देवताओं की शरणगाह रही हैं और वहां उनके भक्त भी आते-जाते तथा प्रवास करते रहे हैं। वे आज के आधुनिक पर्यटकों की तरह चमचमाती मर्सिडीज जैसी गाड़ियों पर नहीं, बल्कि पैदल, खच्चरों या घोड़ों पर ही आवागमन करते थे। लेकिन आज के आधुनिक युग में इन गाड़ियों को सरपट दौड़ने के लिए चौड़े राजमार्ग बनाने पड़ते हैं और पहाड़ों को चीरकर सुरंगें या टनल बनानी होती हैं, जो उनकी मजबूत नींव को अंदर से खोखला कर उनमें दरारें पैदा कर उन्हें कमजोर कर देती हैं।

नेपाल और तिब्बत के क्षेत्रों में कई धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों में बदला जा रहा है और वहां पर्यटकों के ठहरने के लिए पांच सितारा होटल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें बिजली सप्लाई के लिए पहाड़ों के जलप्रपातों पर पनबिजली घर बनाने हेतु बड़े-बड़े बांध बनाए जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में पहाड़ों पर बसी मानव बस्तियों को तबाही झेलने के लिए तैयार रहना होगा।

सवाल यह उठता है कि चीनी नियंत्रण वाले तिब्बत से समुचित चेतावनी चीनी अधिकारियों ने क्यों नहीं दी, जैसा कि नेपाल के विज्ञान मंत्री महावीर पुन ने आरोप लगाया। इसके जवाब में चीन सरकार के प्रवक्ता ने खंडन करते हुए कहा कि चीनी अधिकारियों को इसका अनुभव नहीं हो सकता था, क्योंकि हिमनदीय चट्टानें बिना किसी हलचल के टूटने लगीं और नीचे स्थित नदी के जल को अपनी चपेट में लेने लगीं।

नेपाली मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि चीन के क्षेत्र वाले तिब्बत क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर विकास कार्य हो रहा है जिस कारण पर्वतीय ग्लेशियर तापमान के बढते स्तर को बर्दाश्त नहीं कर रहे और वैश्विक तापमान बढ़ने से वे पिघल कर टूटने लगते हैं। जिसके कारण नीचे के आवासीय क्षेत्रों और वहां बने राजमार्गों को अपने चट्टानी हमले का शिकार बना देते हैं।

साफ है कि इस जल-प्रलय का स्रोत चीन के प्रशासनिक नियंत्रण वाले तिब्बत की पर्वतीय चोटियां थीं, लेकिन इस प्रलय का शिकार नेपाली क्षेत्र हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई।

ऐसी स्थिति में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसे देश के प्रशासनिक तंत्र की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में विकास की ऐसी गतिविधियां न करें और यदि करनी ही हैं तो अपने पड़ोसी देश के क्षेत्रों को किसी प्राकृतिक आपदा की आशंका के बारे में समय रहते चेतावनी जारी करें, ताकि वे अपने बचाव के समुचित व्यवस्था कर सकें। नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई इस प्राकृतिक आपदा ने भारतीयों को चेताया है कि भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों के सीमांत पर्वतीय तिब्बती क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली घर और इसके लिए विशालकाय बांध बना रहा है। इससे न केवल भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों बल्कि बांग्लादेश तक इसकी चपेट में आने और सम्भावित जल-प्रलय की चिंता और गहरी हो गई है।

■■■

चेतावनी

पंकज चतुर्वेदी

यदि हम प्रकृति को क्षतिग्रस्त कर उसमें विकास का रास्ता बनाएंगे तो प्रकृति हमें विनाश की ओर ही धकेलेगी। नेपाल की इस आपदा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिमालय अब और अधिक मानवीय दबाव को सहन करने की स्थिति में नहीं है।

हिमालय का क्रंदन

नेपाल की इस आपदा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिमालय अब और अधिक मानवीय दबाव को सहन करने की स्थिति में नहीं है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक, हमारे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उनके ऊपर अनगिनत खतरनाक झीलें आकार ले रही हैं। यदि भारत सरकार और सम्बंधित राज्य प्रशासन ने अब भी उपग्रह आधारित रियल-टाइम निगरानी तंत्र, सख्त जोनिंग कानून और पारिस्थितिकी आधारित विकास नीतियों को नहीं अपनाया, तो प्रकृति का यह कहर किसी भी समय हमारे बड़े शहरों और बस्तियों को अपनी चपेट में ले सकता है। समय आ गया है कि विकास और पर्यावरण के बीच के इस अंतर्विरोध को समाप्त किया जाए, अन्यथा हिमालय का यह क्रंदन हमारे भविष्य को हमेशा के लिए अंधकारमय कर देगा।

हिमालय की गोद में बसा भारतीय उपमहाद्वीप आज प्रकृति के एक ऐसे प्रकोप के मुहाने पर खड़ा है जिसकी बानगी हाल ही में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर देखने को मिली है, जहां अचानक आई घातक बाढ़ ने सैकड़ों जिंदगियों को निगल लिया। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह तबाही ग्लेशियर के टूटने, तापमान में वृद्धि और पर्वतीय अस्थिरता का परिणाम थी। नेपाल का यह भयावह सैलाब केवल एक पड़ोसी देश की आपदा नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए एक गम्भीर और अंतिम चेतावनी है। यदि हम अपने पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक स्थिति और वहां मंडरा रहे संकटों का समय रहते आकलन नहीं करते हैं, तो भारत के हिमालयी क्षेत्र में भी किसी भी दिन एक ऐसा ही महाप्रलय आ सकता है। जम्मू-कश्मीर पर यहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अत्यंत तीव्र गति से दिखाई दे रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के पृथ्वी विज्ञान विभाग और विभिन्न शोध संस्थानों के आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र के ग्लेशियर, विशेषकर कोल्हाई ग्लेशियर, अभूतपूर्व दर से सिकुड़ रहे हैं। कोल्हाई ग्लेशियर पिछले कुछ दशकों में अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग 22 प्रतिशत से अधिक हिस्सा खो चुका है। तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण कश्मीर घाटी में अनियंत्रित ढंग से 'ग्लेशियल झीलें' बन रही हैं। इन झीलों के उफनने या फटने का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि पंजशीर और पीर पंजाल श्रृंखलाओं में मानवीय हस्तक्षेप, अंधाधुंध निर्माण और जंगलों की कटाई ने पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह असंतुलित कर दिया है। यदि समय रहते इन झीलों के जलस्तर की निगरानी नहीं की गई, तो झेलम बेसिन के आसपास बसे घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं।

केवल हिमानी झीलें ही नहीं, बल्कि कश्मीर की वे ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन झीलें भी अब खतरे के दायरे में हैं जो सदियों से घाटी की जलसुरक्षा की रीढ़ रही हैं। गंगाबल, विशनसर, कृष्णसर, गादसर, तारसर, मारसर, कौंसरनाग, शेषनाग, सतसर, नुंदकोल और अल्पाथर जैसी झीलें वृक्ष रेखा के ऊपर बसी हैं और बर्फ के पिघले पानी तथा वर्षा को संचित कर उसे धीरे-धीरे नीचे झेलम जैसी नदियों, आर्द्रभूमियों और भूजल तक पहुंचाती हैं। यही प्रक्रिया घाटी के अधिकांश लोगों तक दिखाई दिए बिना उनकी जलसुरक्षा सुनिश्चित करती है। परंतु ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, बर्फ की चादर पतली हो रही है और वर्षा-हिमपात का पारम्परिक

समय चक्र बिगड़ चुका है। इन ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों की सहनशक्ति की सीमा पहले से ही बहुत कम है, इसलिए इन्हें एक बुरे मौसम में लगी चोट को ठीक होने में दशकों लग सकते हैं। दुर्भाग्य से, अधिकांश झीलों के लिए अब तक कोई समर्पित प्रबंधन योजना ही नहीं बनाई गई है और जलगुणवत्ता, जैवविविधता व जलवायु संकेतकों की निगरानी बेहद छिटपुट ढंग से हो रही है। कश्मीर के सामने केवल जलवायु और जल प्रबंधन का ही संकट नहीं है, बल्कि इसके ऊपर भूकम्पीय खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा जारी 2025 के राष्ट्रीय भूकंपीय जोनिंग मानचित्र में समूचे हिमालयी चाप को, जिसमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है, अब भारत की सर्वाधिक खतरनाक श्रेणी ‘जोन तख’ में रखा गया है। यह वर्गीकरण भारत-यूरेशिया प्लेटों की निरंतर टक्कर से बनी उस भूगर्भीय वास्तविकता को दर्शाता है जिसके कारण मुख्य हिमालयी थ्रस्ट पर बड़े भूकम्प आना लगभग तय माना जाता है। 2005 का मुज़फ़्फ़राबाद भूकम्प (मैग्नीट्यूड 7.6), जिसमें 80,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कश्मीर घाटी में तेजी से हो रहे अनियमित शहरीकरण, ढलानों पर बढ़ते निर्माण और स्कूलों-अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण भवनों की सीमित भूकंपीय जांच ने इस खतरे को और गम्भीर बना दिया है।

उत्तराखंड का भूगोल इस समय सबसे अधिक संवेदनशील और खतरे के घेरे में है। केदारनाथ आपदा और चमोली के जोशीमठ व ऋषिगंगा घाटी की त्रासदियों से भी यदि हमने सबक नहीं सीखा, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के अनुसार, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 1,000 से अधिक छोटी-बड़ी ग्लेशियल झीलें बन चुकी हैं, जिनमें से कई झीलें ‘फ्लैश फ्लड’ यानी अचानक बाढ़ का कारण बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दून विश्वविद्यालय और पर्यावरणविदों के अध्ययन बताते हैं कि उत्तराखंड में पिछले तीन दशकों में औसत तापमान में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप गंगोत्री और गोमुख जैसे प्रमुख ग्लेशियर प्रति वर्ष 20 से 30 मीटर पीछे खिसक रहे हैं। इन पिघलते ग्लेशियरों के नीचे मलबे और बर्फ का अस्थिर मिश्रण जमा होता जा रहा है और जब कभी जरा सा भी भूकम्पीय कम्पन या बादल फटने की घटना होती है, तो यह मलबा नीचे की ओर आक्रामक गति से बहता हुआ नदियों के किनारे बनी पनबिजली परियोजनाओं और बस्तियों को बर्बाद कर देता है।

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली
सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका
पंजीयन करें
हिंदी विवेक
We Work For Better World
सेवा विवेक ग्रंथ
मौलिक एवं संग्रहणीय ग्रंथ, स्वयं एवं परिजनों के लिए पंजीयन करें
ग्रंथ प्रकाशन का उद्देश्य
भारत की आत्मा ...सेवा। जो केवल सहायता या दान नहीं है।
सेवा का सही अर्थ है कर्तव्य, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय।
सेवा को भावनात्मक कार्य से आगे ले जाकर विचारशील, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना।
सेवा के पीछे की भारतीय दृष्टि, प्रेरणा और दर्शन को उजागर करना।
इस विचार को बल देना कि सेवा व्यक्ति को संस्कारित कर समाज को संगठित एवं सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।
आदर्श सेवा कार्यों को संकलित कर समाज के प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना।
प्रकाशन पूर्व मूल्य
600/-
ग्रंथ का मूल्य
₹700/-
देश के गणमान्य विशेषज्ञों एवं लेखकों की कलम से समृद्ध विषय वस्तु से परिपूर्ण ग्रंथ
ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।
Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK
Bank : State Bank of India
Branch : Charkop
A/C No. : 43884034193
IFSC : SBIN0011694
स्थानीय प्रतिनिधि से सम्पर्क करें
कार्यालय : सहारा नांगरे - 9594991884
Email : hindivivekvargani@gmail.com

करनी चीन की, भरनी नेपाल की !

प्रतिशोध

रामेंद्र सिन्हा

26 अगस्त 2026 को नेपाल-तिब्बत सीमा से नारायणी संगम तक 150 किलोमीटर का इलाका 'डेथ कॉरिडोर' बन गया। एक विशाल हिमनद के टूटने और चीनी निर्माण गतिविधियों के कारण आई प्रलयंकारी बाढ़ ने हजारों जिंदगियां निगल लीं।

26 अगस्त 2026 को नेपाल-तिब्बत सीमा से लेकर भारत की सीमा से सटे नारायणी नदी के संगम तक का लगभग 150 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया, जिसे 'डेथ कॉरिडोर' की संज्ञा दी जा रही है। ये पंक्तियां लिखे जाने तक नेपाल में 5000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 1000 पार है। राहत अभियान में 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। भारत ने भी नेपाल की सहायता के लिए राहत सामग्री और सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष टनल रेस्क्यू टीम भेजी है। दूसरी तरफ, राहत कार्य में बढ़-चढ़ कर शामिल चीन की सरकार तिब्बत में केवल 5 लोगों की मृत्यु की चौंकाने वाली पुष्टि कर रही है। दाल में कुछ तो काला है!

विशेषज्ञों के अनुसार, काठमांडू घाटी से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में तिब्बत सीमा पर नेपाल के लैंगटांग लिरुंग चोटी के पास लगभग 6,000 मीटर ऊंचाई से एक विशाल हिमनद (ग्लेशियर) का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जगह से उखड़ गया और उसके साथ भारी मात्रा में चट्टानें भी टूटकर चीन के तिब्बत क्षेत्र में बहने वाली ल्हेंदे नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में जा गिरीं। अचानक हुई इस घटना से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित अस्थाई हिमनद झीलें ग्लोफ के कारण फट गईं। जब लाखों टन बर्फ और पानी एक साथ भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में पहुंचा, तो उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों को भी चीर दिया। बस, 7 से 16 मिनट के भीतर निचले क्षेत्रों में लगभग 30 फीट ऊंची पानी, गाद, पत्थरों और बोल्डर की प्रलयंकारी लहर ने सब कुछ तबाह कर दिया।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और वैश्विक पर्यावरण निकायों के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा (विशेष रूप से रसुवा-ग्यिरोंग कॉरिडोर) पर आई यह आपदा विकास के नाम पर आधारभूत, ढाचों जैसे सड़कों, सुरंगों और जलविद्युत परियोजनाओं के अंधाधुंध निर्माण का परिणाम है। चीन द्वारा तिब्बत क्षेत्र में और नेपाल की तरफ 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' व व्यापारिक सम्पर्क बढ़ाने के लिए 'पासांग ल्हामु हाईवे' और ग्यिरोंग पोर्ट जैसे भारी कंक्रीट के ढांचे तैयार किए गए।

हीरोशिमा पर गिरे बम से भी अधिक विनाशकारी

प्रारम्भ में इस घटना को एक प्राकृतिक भूकम्प माना गया था, लेकिन अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण और विश्व के भूकम्प विज्ञानियों ने स्पष्ट किया कि यह झटका किसी टेक्टोनिक प्लेट के हिलने से नहीं, बल्कि पहाड़ और हिमनद के गिरने की तीव्र गति के कारण आया था। इस महा-हिमस्खलन से धरती पर 5.2 तीव्रता का एक कृत्रिम भूकम्पीय झटका दर्ज किया गया। इसके झटके इतने तेज थे कि घटना के लगभग 40 मिनट बाद जर्मनी की प्रयोगशाला तक इसके सिग्नल्स दर्ज किए गए। मुख्य घटना के ठीक 3 घंटे बाद, मलबे की बड़ी हलचल के कारण सीस्मिक स्केल पर 4.2 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार, बाढ़ के पानी और मलबे के बहाव से उत्पन्न कुल गतिज ऊर्जा हिरोशिमा बम से भी ज्यादा थी, जबकि हिरोशिमा पर गिरे बम की क्षमता लगभग 15,000 टन टीएनटी के बराबर थी।

सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स वाले इस क्षेत्र में सड़कों-सुरंगों के निर्माण में किए जाने वाले विस्फोटों से, पहाड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। निर्माण के दौरान निकला लाखों टन मलबा प्रायः नदियों में या उनके किनारों पर उड़ेल दिया जाता है। इससे नदियों के प्राकृतिक तल ऊंचे हो जाते हैं, मार्ग संकरा हो जाता है। जब ऊपर हिमनद टूटने जैसी कोई प्राकृतिक घटना होती है, तो संकरी नदी में पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है और मलबे के कारण वह एक सामान्य बाढ़ न रहकर कीचड़ और पत्थरों का प्रलयंकारी सैलाब बन जाता है। चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी मशीनरी, डम्पर और कंक्रीट मिक्सर के बड़े पैमाने पर उपयोग से ब्लैक कार्बन (कालिख) और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो उड़कर पास के हिमनदों पर जमा हो जाता है। सफेद बर्फ की तुलना में काली परत सूरज की गर्मी को ज्यादा सोखती है, जिससे हिमनद तेजी से पिघलने लगते हैं। सुरंगों के निर्माण के कारण प्राकृतिक जल स्रोत और झरने नष्ट हो जाते हैं। पहाड़ों की मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है और वे अंदर से खोखले व शुष्क होने लगते हैं, जिससे वे मूसलाधार बारिश या हिमस्खलन के झटके को झेल नहीं पाते।

आपदा के तुरंत बाद नेपाल में चर्चा शुरू हो गई थी कि चीन द्वारा तिब्बत क्षेत्र में किए जा रहे अंधाधुंध आधारभूत ढांचे और हाइड्रोपावर निर्माण के कारण उत्पन्न भूगर्भीय असंतुलन के कारण ही हिमालय रूठ गया। चीन ने इन आरोपों को तुरंत 'फर्जी खबर' करार दिया। चीनी विदेश मंत्रालय और दूतावास ने नेपाल को समय पर चेतावनी न देने के आरोपों से भी मना किया और कहा है कि विश्व मौसम विज्ञान केंद्र के जरिए आपदा की जानकारी समय रहते साझा की गई थी।

नेपाल को तत्काल बड़ी सहायता और डेटा साझा करके चीन खुद को समस्या के कारण के बजाय संकटमोचक और समाधान के रूप में पेश कर रहा है ताकि उसकी छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। दूसरी ओर, ग्यिरोंग पोर्ट जैसे व्यापारिक मार्ग के ठप होने से भारी आर्थिक नुकसान उठा रहे चीन का मुख्य उद्देश्य इसे शीघ्रातिशीघ्र अपने नियंत्रण में बहाल करना है। चीन नहीं चाहता कि संकट के समय नेपाल पूरी तरह भारत पर निर्भर दिखाई दे। रसुवागढी-ग्यिरोंग सीमा का यह क्षेत्र चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से सटा हुआ है, जो चीन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। चीन राहत कार्यों के बहाने क्षेत्र में अपनी सुरक्षा एजेंसियों, ड्रोन निगरानी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की उपस्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर, नेपाल में जहां लोग अपनों की खोज में विलाप कर रहे हैं, पल-पल की जानकारी विश्व के सामने आ रही है, वहीं सीमापार तिब्बत में इस प्रलय का प्रभाव अभी भी सूचनाओं के काले बादलों और सख्त चीनी पाबंदियों के धुंध में लुप्त है। हिमालय का प्रतिशोध मानवीय हस्तक्षेप, अत्यधिक पर्यटन और अनियंत्रित निर्माण कार्यों के कारण हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं को दर्शाता है।

भूमिका

आशुतोष कुमार सिंह

सहयोग भारत के डीएनए में

हर संकट की घड़ी में भारत ने नेपाल के लिए एक प्रथम उत्तरदाता की भूमिका निभाई है। जब भी नेपाल में कोई आपदा आई है, भारत ने बिना किसी राजनीतिक या भौगोलिक शर्त के मानवीय आधार पर राहत और बचाव सामग्री की आपूर्ति की है।

भारत एक लोकतांत्रिक एवं संवेदनशील देश है। समस्त विश्व को अपना परिवार मानने वाला भारत संकट की घड़ी में सदा-सर्वदा दूसरे देशों की सहायता करता आया है। 26 अगस्त 2026 को नेपाल के भोटे कोशी और रसुवा क्षेत्र में अचानक आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन की त्रासदी पर भारत ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। साथ ही आवश्यक सामग्रियों की खेप भी समय-समय पहुंचाई। अभी भी भारत लगातार नेपाल के लोगों को इस दुख की घड़ी में सहायक बना हुआ है।

भारत की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय ने अत्यंत संवेदनशील, त्वरित और रणनीतिक प्रतिक्रिया दी। भारत ने घटना के पहले ही दिन से नेपाल के प्रति पूर्ण एकजुटता व्यक्त की और पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चलाया। आपदा के समाचार मिलते ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधान मंत्री से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत के लोग नेपाल के अपने बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने नेपाल को हर सम्भव मानवीय, चिकित्सीय और तकनीकी सहायता देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने भारत और नेपाल की बचाव टीमों को जमीनी स्तर पर 24 घंटे समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

इतना ही नहीं विदेश मंत्रालय ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और नेपाल सरकार को सीधी सहायता पहुंचाने के लिए चरणबद्ध कदम उठाए। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक समर्पित 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया। साथ ही काठमांडू और बीजिंग (चीन सीमा पर फंसे श्रद्धालुओं के लिए) स्थित भारतीय दूतावासों में आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू की गई। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री से 28 अगस्त को बातचीत की और राहत कार्यों का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने मीडिया ब्रीफिंग के जरिए समय-समय पर जानकारी दी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे यात्रियों और जलविद्युत परियोजनाओं में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है।

भारत ने किस तरह से नेपाल को त्वरित सहायता एवं सहयोग प्रदान किया इसे निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता हैः

- 26 अगस्त 2026: आपदा के कुछ ही घंटों भीतर भारतीय वायुसेना का सी-130 जे हरक्यूलिस विमान को 10 टन आपातकालीन राहत सामग्री (टेंट, स्लीपिंग बैग, दवाएं, सोलर लैंप) लेकर काठमांडू भेजा गया।
- 27 अगस्त 2026: सी-17 ग्लोबमास्टर विमान से 37.5 टन अतिरिक्त सामग्री भेजी गई, जिसमें भारी जल निकासी पम्प,

जेनरेटर सेट, रसोई किट, टेंट और 8 टन दवाएं शामिल थीं।

- 28 अगस्त 2026: टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना की 5-सदस्यीय टनल रेस्क्यू रेकी टीम और 6-सदस्यीय मेडिकल टीम को 10 टन अतिरिक्त पानी शुद्धिकरण किट व आपूर्ति के साथ भेजा गया।
- 29 अगस्त 2026:13-सदस्यीय विशेषज्ञ टनल रेस्क्यू टीम, 19-सदस्यीय फॉरेंसिक/डीएनए विशेषज्ञों की टीम (शवों की पहचान के लिए) तथा अस्थायी पुल बनाने के लिए बेली ब्रिज नेपाल भेजे गए।

यह पहला अवसर नहीं है, जब भारत अपने पड़ोसी को संकट से उबारने में सहायक साबित हुआ है। जब 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकम्प आया, जिसका केंद्र लामजुंग था। इस आपदा में 9,000 से अधिक लोगों की जान चली गईं और लाखों घर तबाह हो गए। आपदा के मात्र 6 घंटे के भीतर भारत ने 'ऑपरेशन मैत्री' की घोषणा की और राहत कार्य शुरू कर दिया। उस समय भी भारत ने भूकम्प के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आपदा राहत इकाइयों को सक्रिय किया गया। भारतीय वायुसेना का पहला सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 54 कर्मियों, राहत सामग्री और खोजी कुत्तों के दल के साथ काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा।

26 अप्रैल 2015 को 'ऑपरेशन मैत्री' का औपचारिक शुभारम्भ हुआ। भारतीय वायुसेना ने अपने सी-17 ग्लोबमास्टर, आईएल-76 और सी-130 जे विमानों के जरिए 43 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई। एनडीआरएफ की 10 अन्य टीमें तैनात की गईं। वायुसेना और थल सेना के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और एमआई-17 हेलीकॉप्टर दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजे गए। 27 अप्रैल 2015 को भारतीय सेना ने काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में फील्ड अस्पताल और सर्जिकल यूनिट्स स्थापित किए। 18 मेडिकल टीमों में से 6 को तुरंत तैनात किया गया। 10 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स मशीनरी (जेसीबी, क्रेन) के साथ सड़कों से मलबे को साफ करने के लिए पहुंचे। 10,000 कम्बल, 1,000 टेंट और मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। 28 अप्रैल - 30 अप्रैल 2015 के बीच भारतीय वायुसेना ने 43,000 से अधिक फंसे हुए भारतीयों और विदेशी नागरिकों को नेपाल से सुरक्षित निकाला। 1,200 टन से अधिक खाद्य सामग्री, पीने का पानी, दवाइयां और तिरपाल वितरित किए गए।

स्वयं के लिए और अपने परिजनों के लिए ग्रंथ का पंजीयन करें

इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे

- संघ में हो रहे अनगिनत सेवा कार्यों का परिणाम क्या है?
- डॉ. हेडगेवार जी से लेकर डॉ. मोहन भागवत जी तक के सभी सरसंघचालकों का दिशादर्शन...
- राजनीति को केंद्र में न रखकर राष्ट्रीयत्व को क्यों केंद्र में रखा?
- भारत के सम्मुख चुनौतियां और संघ कार्य का प्रभाव
- संघ विचारधारा और परिवर्तन

जैसे विविध मौलिक विषय

ग्रंथ का मूल्य ₹700/-

ईमेल - hindivivekvargani@gmail.com

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483
भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

दही-हंडी

जरा मटकी सम्भाल ब्रजबाला

स्निग्धा अवतंस

गोपी पुकारे, सुनो री यशोदा,
कान्हा ने मेरो मटका फोड़ा।
सखियां मिलकर जाल बिछाए,
पर कान्हा तो हाथ न आए।
छोटी सी मटकी, ऊंचा है टांगा...

कृष्ण जन्मो भयो आज बधाई गाओ री.....के साथ ही पूरा देश भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाता है। इसके बाद दही-हांडी का उत्सव मनाया जाता है, जो बेहद रोचक व रोमांचक होता है।

कोई भी त्यौहार भारतीय संस्कृति का जीवंत उदाहरण है, जिसमें एक है दही-हांडी का उत्सव। दही-हांडी केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि ये एक साथ कई संदेशों को देती हैं। जिसमें एकता, साहस, एकसाथ काम का नियोजन व साथ में इसका आनंद आदि शामिल है। कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर समन्वय दही हांडी में झलकता है। उनकी नटखट लीलाएं, थोड़ी शोखियां, चंचलता, भोलापन , थोड़ी चतुराई आदि को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया जाता है। यह त्योहार महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। दही हांडी के बारे में दंतकथाएं प्रचलित हैं, बालक कृष्ण मक्खन और दही खाना बेहद पसंद करते थे। वे अपने गोप-मित्रों के साथ मिलकर घरों की ऊंची जगहों पर लटके दही के मटके तोड़कर खाया करते थे। यही बाललीला आज दही हंडी के रूप में जीवित है। त्योहार के दिन ऊंची जगह पर एक मटका लटकाया जाता है, जिसमें दही, मक्खन, गुड़ और कभी-कभी पुरस्कार की राशि भी रखी जाती है। युवा गोविंदा दल मानव -पिरामिड बनाकर उस मटके तक पहुंचने और उसे तोड़ते हैं। दही-हंडी का दृश्य देखने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा होते हैं। ढोल-नगाड़ों की थाप पर गोविंदा दल एक-दूसरे के कंधों पर चढ़कर कई स्तरों का पिरामिड बनाते हैं। कभी-कभी यह पिरामिड सात-आठ मंजिला तक ऊंचा हो जाता है। सबसे ऊपर वाला व्यक्ति मटके को तोड़ता है और चारों ओर दही-मक्खन की बौछार हो जाती है। भीड़ जयघोष से गूंज उठती है। यह दृश्य सिर्फ खेल नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति और विश्वास का प्रदर्शन है। महाराष्ट्र में दही हांडी का सबसे भव्य रूप देखने को मिलता है। मुम्बई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे शहरों में दर्जनों दल प्रतिस्पर्धा करते हैं। कई दल पेशेवर स्तर पर तैयार होते हैं। वे महीने भर अभ्यास करते हैं। दही हंडी केवल पुरुषों का उत्सव नहीं रह गया है। अब महिला दल भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। महिला गोविंदा दल अपनी हिम्मत और कौशल से सबको प्रभावित करते हैं। यह सामाजिक बदलाव का संकेत है कि परम्पराएं समय के साथ नए रूप ले रही हैं।

इस त्योहार का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। यह सिखाता है कि कठिन लक्ष्य अकेले नहीं, बल्कि मिलकर प्राप्त किए जा सकते हैं। दही हंडी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं। कभी-कभी लक्ष्य ऊंचा लगता है, लेकिन विश्वास, अभ्यास और साथियों के सहयोग से उसे हासिल किया जा सकता है। जब मटका टूटता है और दही चारों ओर बिखरता है, तो सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक विरासत जीवित होती है। जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा।

50+ YEARS OF MOMENTUM
अर्थ सहकारेण कल्याणम्
दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि.
मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक
सोने तारण कर्ज
जलद कर्ज
कमी प्रक्रिया शुल्क
व्याजदर
९.५०%* वार्षिक
* अटी व शर्ती लागू
TOLL FREE: 1800 233 1919
kalyanjanata.in
KJSBank

भारत गढ़ेंगा राष्ट्रबोध से

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष में युवा शक्ति को राष्ट्र-निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ रहा है। युवाओं को संघ के माध्यम से संस्कारित किया जाता है, राष्ट्रबोध कराया जाता है व उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें तराशा जाता है।

युवा सम्मेलन

आशीष कुमार 'अंशु'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष में युवा शक्ति को राष्ट्र-निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित युवा सम्मेलन, युवा संवाद और युवा संगम इसी दिशा के ठोस प्रयास हैं। इन आयोजनों का केंद्रीय भाव स्पष्ट है- व्यक्ति-निर्माण के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण। युवाओं को केवल उत्साहित नहीं किया जाता, उन्हें राष्ट्रबोध कराया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है और सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से गढ़ा जाता है।

संघ की यह दृष्टि अचानक नहीं बनी। आरएसएस के संस्थापक और प्रथम प.पू. सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने भारत की पराधीनता के मूल कारणों का अध्ययन करते हुए पाया था कि समाज में एकता का अभाव और 'स्वबोध' की कमी ही सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी समझ पर पिछले 100 वर्षों से शाखा के माध्यम से चरित्र-निर्माण का कार्य चल रहा है। शताब्दी वर्ष में इसे व्यापक रूप दिया गया है। पंच परिवर्तन-स्वबोध, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक समरसता और कुटुम्ब प्रबोधन- युवाओं के सामने एक व्यावहारिक मार्ग के रूप में रखा गया है। लक्ष्य 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत है, जिसे विश्वगुरु के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके।

हाल के आयोजन इस दृष्टि को स्पष्ट करते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित युवा सम्मेलन में ओडिशा के सह सम्पर्क प्रमुख डॉ. बसंत पति ने कहा कि यदि युवा राष्ट्रभक्ति और निस्वार्थ सेवा के भाव से कार्य करें तो भारत पुनः विश्वगुरु बन सकता है। उन्होंने युवाओं से स्वबोध जगाने और परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में दशरथ मांझी का उदाहरण दिया गया। संसाधनों और औपचारिक शिक्षा के अभाव में भी एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प से समाज का ऋण चुका सकता है। यही संदेश युवाओं को दिया जा रहा है- समाज का ऋण चुकाना, समाज से उदासीन न रहना।

मोतिहारी में दो दिवसीय युवा संगम में सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी सम्भावना बताया। कानपुर, सरायपाली, संत कबीर नगर, बूंदी, गोवर्धन और अन्य स्थानों पर युवा संवाद हुए। इनमें बौद्धिक सत्र, प्रश्नों के उत्तर और सामाजिक कार्यों से जुड़ने के संकल्प शामिल रहे।

06 सितम्बर को राजस्थान के बयाना में 'वीरता, संस्कृति, संस्कार' विषय पर यूथ कनेक्ट फेस्ट प्रस्तावित है। 16 से 35 वर्ष के युवा इसमें भाग लेंगे। महाराणा सांगा और स्थानीय इतिहास से प्रेरणा लेने का प्रयास होगा। ये आयोजन दिखाते हैं कि संघ युवाओं को केवल भाषण

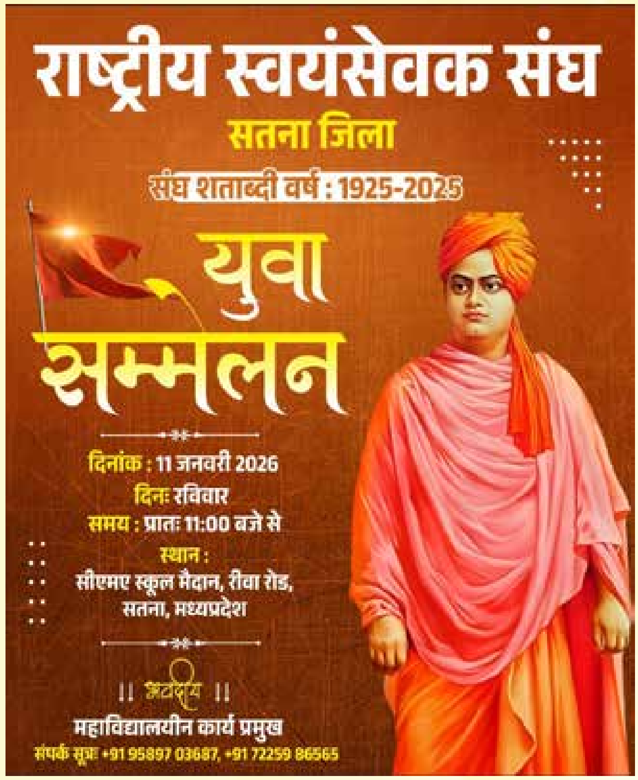

नहीं सुनाना चाहता, उन्हें अपनी जड़ों से जोड़कर रचनात्मक भूमिका के लिए तैयार करना चाहता है।

इसके विपरीत कुछ मंच युवाओं की निराशा को संगठन का कच्चा माल बनाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का उदाहरण इस अंतर को साफ करता है। इसी वर्ष मई में मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक अभियान शुरू किया। बेरोजगार और परीक्षा-पीड़ित युवाओं ने इसे तेजी से अपनाया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की बाढ़ आई, सदस्यता फॉर्म भरे गए और जंतर-मंतर से लेकर अन्य शहरों तक प्रदर्शन हुए। पेपर लीक, परीक्षा अनियमितता और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दे थे। लेकिन तरीका व्यंग्य, नारे, मास्क, धरना और इस्तीफे की मांग का रहा। युवा को कर्तव्य और निर्माण की ओर नहीं, आक्रोश और सड़क की ओर मोड़ा गया।

सीजेपी का स्वभाव मीम्स से आंदोलन की ओर बढ़ना है। स्वयं संस्थापक ने इसे पहले मजाक कहा, फिर यह लाखों युवाओं का मंच बन गया। नारा भी उसी स्वर का है- सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। इसमें परिहास है, लेकिन उसके साथ एक नरेटिव भी बनता है कि व्यवस्था पूरी तरह सड़ी हुई है और युवा केवल पीड़ित तथा विरोधी है। परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की आलोचना आवश्यक है। पर आलोचना जब चरित्र-निर्माण, अनुशासन, परिवार और राष्ट्रबोध से कटी रहे तो युवा की ऊर्जा विरोध में खर्च हो जाती है, समाधान में नहीं। कुछ प्रदर्शनों में टकराव, अव्यवस्था और केवल दबाव बनाने की भाषा भी दिखी। इससे युवा आक्रामक तो बन सकते हैं, जिम्मेदार नागरिक कम।

दोनों दृष्टिकोणों का अंतर मूलभूत है। संघ युवा को कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाना चाहता है। शाखा समयबद्धता, संयम, शारीरिक और मानसिक अनुशासन सिखाती है। इतिहास के वीर नायकों से प्रेरणा ली जाती है। परिवार को राष्ट्र की पहली पाठशाला माना जाता है। सामाजिक समरसता का अर्थ व्यवहार में भेद मिटाना है। पर्यावरण और स्वदेशी को जीवनशैली से जोड़ने की बात की जाती है। युवा से कहा जाता है कि वह समाज का ऋणी है और उस ऋण को सेवा से चुकाए।

सीजेपी जैसी धारा युवा को मुख्यतः व्यवस्था का आलोचक और दावेदार बनाती है। सोशल मीडिया की तेजी से भीड़ जुटती है, नारे चलते हैं, एक मंत्री के त्यागपत्र तक मांग केंद्रित रहती है। शिक्षा और रोजगार के संकट को केवल सरकार-विरोध का औजार बना देने से युवा में स्थायी निराशा और विखंडन बढ़ सकता है। एक तरफ व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के अंग के रूप में गढ़ने का प्रयास है, दूसरी तरफ उसे व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा करने का। एक तरफ संस्कृति और संस्कार को शक्ति माना जाता है, दूसरी तरफ व्यंग्य और आक्रोश को पहचान।

संघ के युवा सम्मेलनों में प्रश्न पूछे जाते हैं, संवाद होता है, पर दिशा राष्ट्रहित की रहती है। युवा को बताया जाता है कि 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के साथ सामूहिक कर्तव्य भी जुड़े। स्वबोध के बिना संस्थान भी विदेशी आदतों को ढोते रहते हैं। संघ युवा से कहता है कि भीतर की पहचान जगाओ, परिवार संभालो, पर्यावरण बचाओ, कानून मानो और समाज में समरसता बढ़ाओ।

युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है। परीक्षाओं की स्वच्छता और रोजगार के अवसर अवश्य सुधारे जाने चाहिए। प्रश्न यह है कि युवा को किस दिशा में मोड़ा जाए। संघ शताब्दी वर्ष में उसे रचनात्मक और सांस्कृतिक दिशा देने का प्रयास कर रहा है। यदि युवा को केवल दिग्भ्रमित किया जाए, आक्रामक बनाया जाए और व्यंग्यात्मक नरेटिव से व्यवस्था-विरोध सिखाया जाए तो ऊर्जा बिखर जाएगी। व्यक्ति-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण साथ चलें तभी भारत अपनी सभ्यतागत भूमिका निभा सकेगा। युवा सम्मेलन इसी समझ को व्यवहार में उतारने का मंच हैं। ■■■

महंगी रसोई
डगमगाता आर्थिक संतुलन

महंगाई

सतीश सिंह

चीनी, प्याज और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अचानक उछाल केवल रसोई का मामला नहीं है। यह आम आदमी की क्रयशक्ति, पारिवारिक बचत, बैंकों की जमा वृद्धि, ऋण वितरण और देश की आर्थिक स्थिरता तक को प्रभावित करता है।

चीनी की कीमतों में हाल की तेजी के पीछे उत्पादन, मौसम, मांग और बाजार व्यवहार का मिला-जुला प्रभाव है। जुलाई से अगस्त 2026 के बीच खुदरा चीनी का औसत मूल्य लगभग 48 रुपए से बढ़कर लगभग 56 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। चालू सत्र में चीनी उत्पादन का शुरुआती अनुमान लगभग 343 लाख टन था, जिसे बाद में घटाकर लगभग 306 लाख टन कर दिया गया। गन्ने की फसल में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसे रोग, अत्यधिक बारिश से जलभराव, त्योहारों से पहले मांग में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति में कमी तथा कुछ कारोबारियों की जमाखोरी ने कीमतों पर दबाव बढ़ाया। इस बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन आंकड़े इस धारणा का समर्थन नहीं करते। एथेनॉल के लिए प्रयुक्त चीनी का हिस्सा 2022-23 के लगभग 12 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में करीब 9 प्रतिशत रह गया है। हालिया तेजी में कृत्रिम रूप से आपूर्ति रोकने और सट्टेबाजी की भूमिका अधिक दिखाई देती है। सरकारी कार्रवाई के बाद एक्स-मिल कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट इसका संकेत है।

प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की प्रकृति कुछ अलग है। वर्ष 2025-26 में उत्पादन लगभग 307.37 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के बराबर है। इसके बावजूद कीमतें बढ़ी हैं। इसका कारण देशव्यापी कमी से अधिक मौसमी दबाव, त्योहारों की मांग, परिवहन लागत और भविष्य में आपूर्ति घटने की आशंका है। देश में वैज्ञानिक भंडारण क्षमता अभी भी अपर्याप्त है. इसलिए प्याज जल्दी खराब हो जाता है।

मानसून में देरी होने पर खरीफ की बुआई और मंडियों में नई फसल की आवक प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप किसान को उत्पादन स्थल पर कम मूल्य मिलता है, जबकि शहर का उपभोक्ता महंगा प्याज खरीदता है। अगस्त 2026 में प्याज का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य लगभग 38 रुपये प्रति किलोग्राम था। दूध की कीमतें पशु आहार, हरा और सूखा चारा, खली, मक्का, परिवहन, बिजली, श्रम तथा पशु चिकित्सा की लागत से प्रभावित होती हैं। मुम्बई में सितम्बर 2026 से तबेला दूध का थोक मूल्य 93 रुपए से बढ़ाकर 102 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा की गई है। उत्पादकों के अनुसार पशु आहार की कुछ किस्मों के दाम 25 प्रतिशत तक बढ़े हैं। त्योहारों में दूध, दही, पनीर, घी और मिठाइयों की मांग बढ़ने से कीमतों पर भी दबाव पड़ता है। अभी कीमतों का दबाव केवल इन तीन वस्तुओं तक सीमित नहीं है। क्षेत्र और शहर के अनुसार खाद्य तेल, चाय, कॉफी, मसाले, आटा, चावल, दालें, फल, अंडे, मांस, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद महंगे हुए हैं। दूध और चीनी की कीमत बढ़ने से

चाय, मिठाई, बेकरी उत्पाद, आइसक्रीम और रेस्तरां का भोजन भी महंगा हो जाता है। ईंधन, परिवहन, पैकेजिंग और मजदूरी की लागत बढ़ने पर साबुन, टूथपेस्ट तथा घरेलू सफाई की वस्तुओं तक इसका प्रभाव पहुंचता है।

महंगाई रुपए के अंकित मूल्य को नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक क्रयशक्ति को घटाती है। जो सामान पहले 100 रुपए में मिलता था, यदि वही अब 110 रुपये में मिलता है तो रुपए की क्रयशक्ति लगभग 9 प्रतिशत कम हो जाती है। वेतनभोगियों, पेंशनभोगियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की आय कीमतों के अनुपात में नहीं बढ़ती। इसलिए परिवार पहले गैर-आवश्यक खर्च रोकते हैं और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा या पोषण से समझौता करने लगते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार का मासिक खाद्य बजट 12,000 रुपए है और कीमतें 10 प्रतिशत बढ़ती हैं, तो उसे समान मात्रा खरीदने के लिए 1,200 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। आय स्थिर रहने पर यह रकम बचत, निवेश या अन्य खर्चों से निकलेगी। गरीब परिवार दूध, फल और प्रोटीन वाली वस्तुओं की खपत घटा सकते हैं। इससे महंगाई, आर्थिक समस्या के साथ पोषण और मानव विकास की चुनौतियां भी बन जाती हैं।

घरेलू बचत में कमी का प्रभाव बैंकिंग प्रणाली पर पड़ता है। यदि परिवारों की आय का अधिक भाग खर्च में चला जाए, तो बचत खाते और सावधि जमा में कम राशि जमा होती है। जब बैंक की जमा बढ़ोत्तरी ऋण की मांग से पीछे रह जाती है, तो उन्हें अधिक दरों पर जमा जुटानी पड़ती है। यह उनके संसाधनों की लागत बढ़ाता है, जिससे आवास, वाहन, कृषि और व्यवसाय ऋण महंगे हो सकते हैं। साथ ही, ऋण देने योग्य संसाधनों की कमी निवेश और रोजगार के अवसरों को कम कर सकती है।

महंगाई से उपभोक्ता मांग कमजोर पड़ती है, कारोबार की लागत बढ़ती है और कर्मचारी अधिक वेतन की मांग करते हैं। यदि कम्पनियां बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डालती हैं, तो महंगाई दूसरे क्षेत्रों में फैल जाती है। रिजर्व बैंक को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ सकती हैं, जिससे निवेश घटता है। सरकार को सब्सिडी, बफर स्टॉक और राहत योजनाओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे राजकोषीय दबाव बढ़ सकता है।

समाधान के लिए सरकार को उत्पादन और बाजार दोनों स्तरों पर काम करना होगा। प्याज के आधुनिक भंडारगृह, शीत श्रृंखला, चारा बैंक, बेहतर बीज, फसल बीमा तथा मौसम पूर्वानुमान को मजबूत किया जाए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए मौलिक एवं संग्रहणीय पुस्तक

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित
'हिंदी विवेक' द्वारा प्रकाशित

हम संघ में क्यों हैं...

संघ विचारों की मूल प्रेरणा, संघकार्य को समझने की प्रक्रिया और इन सभी से संघ स्वयंसेवकों को अनायास मिलनेवाले राष्ट्रबोध और कर्तव्यबोध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

पंजीयन करें

पुस्तक का मूल्य ₹250/-

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483, भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

UNITED LIBERATION COUNCIL

Assalamu'Alaikum, August 23rd, 202

We have already warned Kashmiri Pandiths not to become scapegoats or ac
as pawns for this illegal regime, or else face the consequences. We also wan
to clarify that we are not against those Kashmiri Pandiths who stayed in th
valley and did not fall for the false promises of the then Governo
Jaghmohan. Those Pandiths are safe and nobody opposes them. However
all those Pandiths who migrated from the valley are hypocrites and traitors
They are targeted not because of their religion but because of thei
traitorous actions and conduct. Even now, they are playing into the hands o
this illegal regime. These Migrant Pandiths are the white-collar terrorist
working for their masters in Delhi. As already warned, wherever you are an
wherever ... We gave you time to
reform, ... implement the RS
agenda ... enly, but strikes whe
it must ...

- Sushant. Din...
- Rohit. Bha...
- Sahil. L 7, ...
- Sawan. Di...
- Shikha H. ...
- Ashwani. ... Silver Color

उगते सूर्य को फिर अस्त करने का षड़यंत्र

डॉ. अर्पण जैन 'अविचल'

कश्मीरी पंडितों को मिल रहे धमकी-पत्रों और पोस्टरों को गम्भीरता से लेना आवश्यक है। यदि इनमें कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम, घर और वाहन जैसी व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं, तो यह सामान्य धमकी से कहीं अधिक गम्भीर विषय है।

सन् 1980 के दशक के उत्तरार्ध में यानी 1989-1990 में भी कश्मीरी पंडितों के दमन और उनके बड़े पैमाने पर पलायन का इस क्रूर इतिहास लिखा गया, जिसकी शुरुआत आतंकवाद और अलगाववाद के उभार के साथ हुई थी। 19 जनवरी, 1990 को रात लगभग साढ़े 8 बजे कश्मीर की मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान हो रहे थे। सड़कों पर नारे लगाए जा रहे थे। कुछ नारे कश्मीरी पंडित महिलाओं के विरुद्ध भी लग रहे थे। इन हालात में कुछ कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ कश्मीर से जाने लगे। अगले दिन हालात और बुरे होने लगे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था। 1990 में 808 कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीर छोड़कर नहीं गए, फिर उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ वहां पर और फिर घाटी ने उनका रुदन सुना। जनवरी-फरवरी 1990 तक बहुत से कश्मीरी पंडित अपना देश कश्मीर छोड़कर जम्मू, दिल्ली या अन्य स्थानों पर चले गए। उस बर्बरता को भी इसी कश्मीर घाटी ने अपनी नग्न आंखों से देखा और उन परिवारों की आंखों में आज भी वह मंजर जिंदा है, उन्हें आज तक उस दर्द का पता चलता है।

वर्तमान की बात करें तो कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास का प्रश्न केवल रोजगार या आवास का विषय नहीं है। यह उस विश्वास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसमें एक विस्थापित समुदाय अपनी जन्मभूमि में दोबारा सामान्य जीवन जीने की सम्भावना देखता है। पिछले कुछ दशकों में कश्मीरी पंडित समुदाय ने विस्थापन, असुरक्षा और सामाजिक विघटन का कठिन दौर देखा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक कश्मीरी पंडित कर्मचारी घाटी में लौटकर अपने दायित्व निभा रहे हैं, तब उन्हें मिलने वाली कथित आतंकी धमकियां चिंता का गम्भीर विषय बन जाती हैं।

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कथित धमकी-पत्रों और पोस्टरों के सामने आने के समाचारों ने इस चिंता को और गहरा किया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी नामक संगठन की ओर से कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को निशाना बनाते हुए धमकी भरे संदेश प्रसारित किए गए हैं। विभिन्न रिपोर्टों में इस संगठन को लश्कर-ए-तैयबा का कथित मुखौटा संगठन बताया गया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री और उसके स्रोत की आधिकारिक पुष्टि तथा उसकी प्रामाणिकता की जांच महत्त्वपूर्ण है और किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले सुरक्षा एजेंसियों की जांच की प्रतीक्षा किया जाना चाहिए।

लेकिन यदि इन धमकियों में से कुछ भी वास्तविक है, तो मामला अत्यंत गम्भीर है। क्योंकि यह केवल किसी व्यक्ति को धमकी देने तक सीमित नहीं है। कथित तौर पर कर्मचारियों के नाम, उनके मकान नम्बर, गली नम्बर और वाहनों के नम्बर तक सार्वजनिक किए जाने की बात सामने आई है। किसी व्यक्ति की ऐसी पहचान योग्य निजी जानकारी को धमकी के साथ सार्वजनिक करना, उसकी निगरानी, भय और सम्भावित हिंसा की आशंका को कई गुना बढ़ा देता है।

सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को घाटी में काम करने को लेकर धमकाया जा रहा है। कथित धमकी-पत्रों में उन्हें गद्दार और देशद्रोही जैसे शब्दों से सम्बोधित किए जाने की बात कही गई है। उन्हें अपनी गतिविधियां बदलने अथवा पीछे हटने की चेतावनी दिए जाने के भी समाचार हैं।

आतंकी संगठनों की भाषा में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नया नहीं है। आतंकवाद केवल हथियारों के माध्यम से हिंसा नहीं करता, बल्कि भय का वातावरण तैयार करके भी अपने उद्देश्य पूरे करने का प्रयास करता है। किसी समुदाय के लोगों को 'गद्दार' या 'देशद्रोही' घोषित करना, उनके सामाजिक अस्तित्व और सार्वजनिक पहचान पर हमला करने का एक तरीका हो सकता है। यदि किसी पोस्टर में केवल किसी समुदाय के विरुद्ध सामान्य धमकी दी जाती है तो भी वह गम्भीर अपराध है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम, मकान नम्बर, गली, वाहन नम्बर अथवा अन्य पहचान योग्य जानकारी सार्वजनिक की जाए, तो संकट और अधिक व्यक्तिगत हो जाता है। ऐसी जानकारी का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना हो सकता है कि 'हम तुम्हें जानते हैं', 'हम तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं' और 'हम तुम तक पहुंच सकते हैं।'

भय पैदा करने की दृष्टि से यह अत्यंत प्रभावी तरीका हो सकता है। व्यक्ति अपने कार्यालय जाने, घर से निकलने, बच्चों को स्कूल भेजने या बाजार जाने तक को लेकर आशंकित हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह पता लगाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि कथित पोस्टरों में प्रकाशित जानकारी आतंकियों तक कैसे पहुंची? यदि सरकारी या प्रशासनिक रिकॉर्ड से किसी प्रकार की संवेदनशील जानकारी लीक हुई है, तो यह अलग स्तर की सुरक्षा चुनौती है। और यदि यह जानकारी खुले स्रोतों, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से एकत्र की गई है, तब भी साइबर निगरानी और डिजिटल सुरक्षा की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। ■■■

प्रो. अलकेश चतुर्वेदी

राष्ट्र केवल साक्षर हाथों से नहीं बनते, वे सजग मस्तिष्क, संस्कारित हृदय और मातृभूमि के प्रति उत्तरदायी नागरिकों से बनते हैं।

विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितम्बर

साक्षरता से आगे: राष्ट्र साक्षरता

विश्व साक्षरता दिवस पर हम प्रायः यह गणना करते हैं कि भारत कितना साक्षर हुआ, कौन-सा राज्य आगे है और कौन पीछे। किंतु एक अधिक मौलिक प्रश्न यह है कि यदि भारत शत-प्रतिशत साक्षर हो जाए तो क्या वह स्वतः सुशिक्षित और राष्ट्र-सचेत भी हो जाएगा? क्या अक्षर-ज्ञान अपने आप सामाजिक दायित्व, सांस्कृतिक आत्मबोध और राष्ट्रभाव उत्पन्न कर देता है? संभवतः नहीं। अक्षर पढ़ लेना साक्षरता है, उसका आशय समझना शिक्षा है, सत्य-असत्य का विवेक सुशिक्षा है और अर्जित ज्ञान को राष्ट्र एवं लोकमंगल में नियोजित करना विद्या है। भारत ने साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु में देश की साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत है। मिजोरम 98.2 प्रतिशत, नागालैंड 95.7 प्रतिशत और केरल 95.3 प्रतिशत जैसे राज्य अग्रणी हैं। यह उपलब्धि अभिनंदनीय है, किंतु क्या उच्च साक्षरता राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक स्वाभिमान और नागरिक कर्तव्यबोध की भी स्वतः प्रत्याभूति है? यदि ऐसा होता तो उच्च साक्षरता वाले किसी समाज में पृथकतावाद, हिंसक अतिवाद, मादक पदार्थों की समस्या अथवा सांस्कृतिक विच्छेदन दिखाई ही नहीं देता। अतः साक्षरता आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं; शिक्षा आवश्यक है, किंतु शिक्षा की दिशा उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है।

केरल इस विमर्श का उदाहरण है। वहां शिक्षा-विस्तार में त्रावणकोर-कोचीन के शासकों, समाज-सुधारकों, स्थानीय समुदायों और ईसाई मिशनरियों की भूमिका रही। मिशनरियों ने विद्यालय, मुद्रणालय और आधुनिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित कीं। किंतु औपनिवेशिक मिशनरी शिक्षा को केवल निष्काम शिक्षा-सेवा मानना इतिहास को अधूरा पढ़ना होगा। विभिन्न मिशनों के घोषित उद्देश्यों में शिक्षा के साथ ईसाई मत-प्रसार और मतांतरण भी सम्मिलित थे। शिक्षा, चिकित्सा और सेवा ने अनेक क्षेत्रों में समाज तक पहुंच का मार्ग बनाया और उसके साथ धार्मिक-सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। 2011 की जनगणना में केरल की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या ईसाई थी। वास्तविक प्रश्न किसी भारतीय ईसाई की राष्ट्रनिष्ठा का नहीं, बल्कि शिक्षा अथवा सेवा को यदि किसी व्यक्ति को उसकी पूर्वज-स्मृति और सांस्कृतिक मूल से विच्छिन्न कर मतांतरण का माध्यम बनाया जाए तो उस प्रक्रिया की समीक्षा का है।

पूर्वोत्तर भारत में यह प्रश्न और गम्भीर ऐतिहासिक आयाम ग्रहण करता है। नागा क्षेत्रों में अमेरिकी बैपटिस्ट मिशनरियों ने विद्यालय, मुद्रण और स्थानीय भाषाओं के लेखन में योगदान दिया, किंतु शिक्षा के साथ ईसाई मत-प्रसार भी उनके मिशन का अंग था। समय के साथ नागालैंड और मिजोरम ईसाई-बहुल प्रदेश बने। इसी भूभाग ने औपनिवेशिक काल के बाद पृथक राजनीतिक अस्मिता और सशस्त्र आंदोलनों की दीर्घ चुनौती भी देखी। इसका अर्थ यह नहीं कि ईसाई होना पृथकतावादी होना है, बल्कि प्रश्न यह है कि इतनी उच्च साक्षरता के बावजूद यदि राष्ट्रीय

एकात्मता की चुनौती बनी रहे तो शिक्षा की दिशा और उसके सांस्कृतिक आधार पर विमर्श क्यों न हो? मणिपुर के संदर्भ में कुकी समाज का उल्लेख भी आता है। कुकी कोई धर्म नहीं, अनेक जनजातीय समूहों की व्यापक सांस्कृतिक पहचान है और वर्तमान में उनमें ईसाई धर्म का व्यापक प्रभाव है। किसी सम्पूर्ण समुदाय को राष्ट्र-विरोधी कहना न तथ्यसम्मत है, न आवश्यक, किंतु जहां कोई सशस्त्र अथवा पृथकतावादी संगठन भारत की सम्प्रभुता या संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देता है, वहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि शिक्षा ने व्यक्ति को अक्षर तो दिए, पर क्या मातृभूमि से एकात्मता भी दी? डिग्री मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकती है, किंतु राष्ट्रबोध के बिना वही प्रशिक्षित बुद्धि राष्ट्र-निर्माण की शक्ति बनेगी, इसकी कोई स्वतः प्रत्याभूति नहीं है।

भारतीय ज्ञान-परम्परा इस संदर्भ में विलक्षण मार्गदर्शन देती है। हमारे यहां शिक्षा केवल जीविकोपार्जन की व्यवस्था नहीं थी। तैत्तिरीय उपनिषद् का दीक्षांत संदेश-सत्यं वद, धर्मं चर-ज्ञान को आचरण से जोड़ता है। गुरुकुल, पाठशाला, तोल और चतुष्पाठी केवल अक्षर नहीं देते थे, मनुष्य को परिवार, समाज, प्रकृति और संस्कृति से जोड़ते थे। भारतीय दृष्टि में ज्ञान का अंतिम परीक्षण परीक्षा-कक्ष में नहीं, आचरण में होता था। वस्तुतः शिक्षा कभी मूल्य-निरपेक्ष नहीं होती। जो बालक को अक्षर देता है, वह उसे संसार को देखने की दृष्टि भी देता है। शिक्षा यदि अपनी संस्कृति के प्रति गौरव जगाती है तो सभ्यता की निरंतरता बनती है, यदि अपनी जड़ों के प्रति हीनता उत्पन्न करती है तो सांस्कृतिक विस्मृति का कारण बन सकती है। शायद सबसे बड़ी निरक्षरता वह नहीं जिसमें मनुष्य पुस्तक नहीं पढ़ पाता, सबसे गहरी निरक्षरता वह है जिसमें मनुष्य संसार तो पढ़ लेता है, किंतु अपने राष्ट्र और सभ्यता को पढ़ना भूल जाता है।

स्वतंत्र भारत ने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और अब यूएलएलएएस जैसे कार्यक्रमों से अक्षर-ज्ञान का अभूतपूर्व विस्तार किया है। अब अगली यात्रा लिटरेसी से सिविलाईजेशन लिटरेसी और नेशनल लिटरेसी की होनी चाहिए। आज का भारतीय अक्षर-साक्षर के साथ डिजिटल-साक्षर, संवैधानिक-साक्षर, सांस्कृतिक-साक्षर और राष्ट्र-साक्षर हो। इंटरनेट चलाना पर्याप्त नहीं, सत्य और दुष्प्रचार में भेद भी आना चाहिए; संविधान में अधिकार जानना पर्याप्त नहीं, कर्तव्यों का बोध भी होना चाहिए; विश्व को जानना आवश्यक है, किंतु अपनी मातृभूमि और पूर्वजों से अपरिचित होना शिक्षा की पूर्णता नहीं है।

आपकी आवाज को बुलंद करने वाली
सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

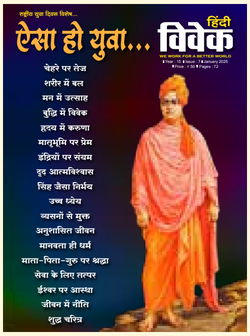

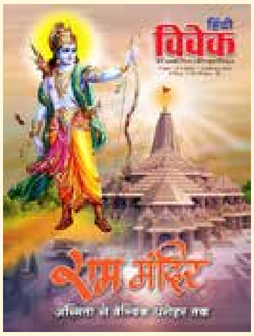

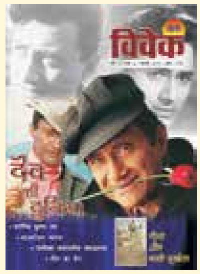

हिंदी
विवेक
" We Work For A Better World"

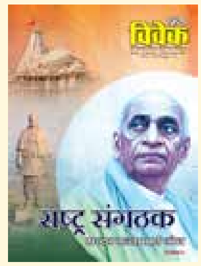

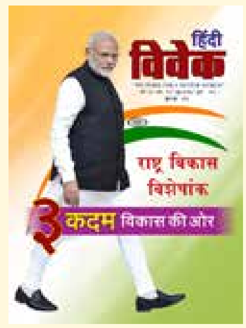

सदस्यता शुल्क

- वार्षिक मूल्य : रु. 500/-
- त्रैवार्षिक मूल्य : रु. 1,200/-
- पंचवार्षिक मूल्य : रु. 1,800/-
- संरक्षक मूल्य : रु. 25,000/-
- विदेशी सदस्यता शुल्क वार्षिक : रु. 5,000/-

खुद ग्राहक बनें व बनाएं

- जन्म दिन तथा अन्य समारोहों में हिंदी विवेक उपहार के रूप में भेंट करें।
- मित्रों, रिश्तेदारों तथा शुभचिंतकों को हिंदी विवेक की सदस्यता प्रदान करें।
- अपने दिवंगत स्नेहीजनों की स्मृति में 11, 21, 51 या 101 पाठकों को सदस्यता दें।
- विवाह के अवसर पर सदस्यता उपहार में दें।
- नववर्ष की शुभकामना के रूप में ग्रीटिंग कार्ड के स्थान पर हिंदी विवेक का सदस्यता रसीद प्रदान करें।

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

हिंदी विवेक कार्यालय

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर 10, सेक्टर - 2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे,
हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - 400067

सम्पर्क : +91 95949 91884

hindivivekvargani@gmail.com / hindivivekadvt@gmail.com

विश्व कप हॉकी में भारत का स्थान

हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम के वेव्रे और नीदरलैंड्स के एमस्टेलवीन में हुआ। यह 52 साल बाद विश्व कप के शीर्ष 5 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

भारत जैसे विशाल राज्य में अनेक देशी-विदेशी खेलों को खेला जाता है। इनमें अनेक इंडोर-आउटडोर खेल शामिल हैं। इन सारे विविध खेलों में राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को मान्यता प्राप्त है। हॉकी में दो मुख्य एशियाई देशों भारत और पाकिस्तान का दबदबा था तो जब इस खेल में विश्व चैम्पियन की खोज शुरु हुई तो यह दायित्व भारत और पाकिस्तान को सौंपा गया था। इस तरह 1971 में पुरुष विश्व कप हॉकी की शुरुआत हुई। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत पहली बार साल 1971 में हुई थी। स्पेन में आयोजित इस पहले टूर्नामेंट में भारत ने केन्या को हराकर कांस्य पदक जीता और तीसरे स्थान पर रहा था। पहली दो प्रतियोगिताएं 2 वर्षों के अंतराल पर हुईं। 1973 में नीदरलैंड में आयोजित हमारी टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन

राजीव रोहित

मेजबान नीदरलैंड से पेनाल्टी शूट आऊट में हार गई। 1975 के बाद से इसे प्रति चार वर्षों में आयोजित किया जाने लगा। इसी वर्ष (1975) में मलेशिया में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुआलालंपुर में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। निर्णायक गोल हॉकी के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार ने किया था। यह एक मात्र जीत की विजयी टीम के कप्तान अजित पाल सिंह थे। वस्तुस्थिति यह है कि यह अब तक पुरुष हॉकी विश्व कप इतिहास में ओलम्पिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत का एकमात्र खिताब है। कहा जा सकता है कि पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत का इतिहास बेहद उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। भारत ने सभी 16 विश्व कप

प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। वस्तुतः 1978 में ही अर्जेटिना में स्ट्रो टर्फ मैदान पर आयोजित प्रतियोगिता में भारत सहित सभी एशियाई देशों के प्रदर्शन में गिरावट शुरु हो गई थी। भारत के पास इस बड़े टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा बार आयोजित करने का रिकॉर्ड भी है। भारत ने चार बार(1982, 2010, 2018 और 2023) विश्व कप की मेजबानी की है। अपनी मेजबानी में 1982 में छठे, 2010 में आठवें, 2018 में फिर छठे एवं 2023 में नवें स्थान पर रहा। 1975 के बाद विश्व कप की खोज में जुटा भारत का सबसे खराब प्रदर्शन 1986 में रहा जब यह 12वें स्थान पर रहा था। हम आज भी एक विश्व कप के लिए तरस रहे हैं। जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी में भारत ने अवश्य दो बार अर्थात वर्ष 2001 में वर्ष 2016 में अपनी मेजबानी में विश्व विजेता का खिताब जीता है और एक बार फिर वर्ष 2025 में अपनी मेजबानी में कांस्य पदक जीता है।

इसी प्रकार महिला विश्व हॉकी के परिदृश्य में भारत की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी रही थी। 1974 में फ्रांस में आयोजित पहले महिला विश्व कप हॉकी में भारत ने सेमी-फाइनल तक की यात्रा तय की थी और शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया था। महिला जूनियर विश्व हॉकी में भारत ने एक ही बार 2013 में इंग्लैंड को पेनाल्टी शूट में हराकर कांस्य पदक जीता था। 2025 में यह दसवें स्थान पर रही।

इस वर्ष हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम के वेव्रे और नीदरलैंड्स के एमस्टेलवीन में हुआ। भारतीय पुरुष टीम बेल्जियम से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर आठवें स्थान पर रही। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराकर पांचवां स्थान प्राप्त किया। यह 52 साल बाद विश्व कप के शीर्ष 5 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम के लगातार दो पदक (कांस्य) जीतने के बाद आधार तो मजबूत हुआ है, लेकिन विश्व कप चैम्पियन बनने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े सुधारों की आवश्यकता है। भारतीय हॉकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बादशाहत बनाए रखने और लगातार शीर्ष पर रहने के लिए जमीनी स्तर के विकास, आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान देना होगा। हमें ऐसे बहुत सारे कदम उठाने होंगे जो भारतीय हॉकी के कल्याण के लिए बेहद आवश्यक साबित होंगे। उदाहरण के लिए स्कूली स्तर पर हॉकी नर्सरी का विस्तार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से पंजाब, ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत सभी राज्यों में इस प्रकार की नर्सरी खोले जाने की ज्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार स्कूलों में टर्फ (स्ट्रो-टर्फ) की उपलब्धता बढ़ानी होगी, क्योंकि आज की आधुनिक हॉकी मिट्टी या घास पर नहीं, बल्कि केवल सिंथेटिक टर्फ पर खेली जाती है। भारत में अभी भी एस्ट्रो-टर्फ मैदानों की संख्या सीमित है। खिलाड़ियों को बचपन से ही टर्फ पर खेलने की आदत होनी चाहिए ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ढलने में समय न लगे। घरेलू टूर्नामेंटों का आधुनिकीकरण भी एक आवश्यकक कदम साबित हो सकता है। राष्ट्रीय और घरेलू स्तर के सभी टूर्नामेंट अनिवार्य रूप से अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले मैदानों और गेंदों के साथ खेले जाने चाहिए। भारत को ड्रैग-फ्लिक,पेनाल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलने की क्षमता और गोलकीपिंग जैसे विशेष विभागों के लिए भारत अथवा विदेशों के सर्वश्रेष्ठ कोचों को स्थायी रूप से नियुक्त करना चाहिए। आधुनिक हॉकी अब केवल शारीरिक क्षमता का खेल नहीं है, बल्कि यह डेटा और वीडियो एनालिसिस का खेल है। विपक्षी टीम की कमजोरियों को पकड़ने के लिए हाई-टेक सॉफ्टवेयर और डेटा विश्लेषकों की भूमिका बढ़ानी होगी। भारतीय टीम अक्सर बड़े मैचों के आखिरी मिनटों में दबाव में आकर गोल खा जाती है। खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और दबाव झेलने की क्षमता को मजबूत करने के लिए पूर्णकालिक मनोवैज्ञानिक टीम के साथ होने चाहिए। उपरोक्त कदमों के अलावा

खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए अत्याधुनिक रिकवरी टूल और विश्व स्तरीय फिजियोथेरेपिस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। क्रिकेट की आईपीएल की तरह, हॉकी इंडिया लीग का लगातार और बिना रुकावट के आयोजन होना बेहद आवश्यक है। इससे युवा खिलाड़ियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनुभव मिलता है और उनका भय खत्म होता है।

भारतीय हॉकी को वैश्विक स्तर पर उच्च शीर्ष स्थानों पर पहुंचाने के लिए मेजर ध्यांचंद के.डी.सिंह बाबू,ललित उपध्याय की परम्परा को आगे बढ़ानेवाले अजीत पाल सिंह, अशोक कुमार, बलबीर सिंह सीनियर,परगट सिंह,मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, दिलीप तिर्की, अमित रोहिदास, बीरेंद्र लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, रानी रामपाल, सविता पूनिया,नवजौत कौर जैसे और अधिक से अधिक खिलाड़ियों की खेप की खोज करनी होगी। ■■■

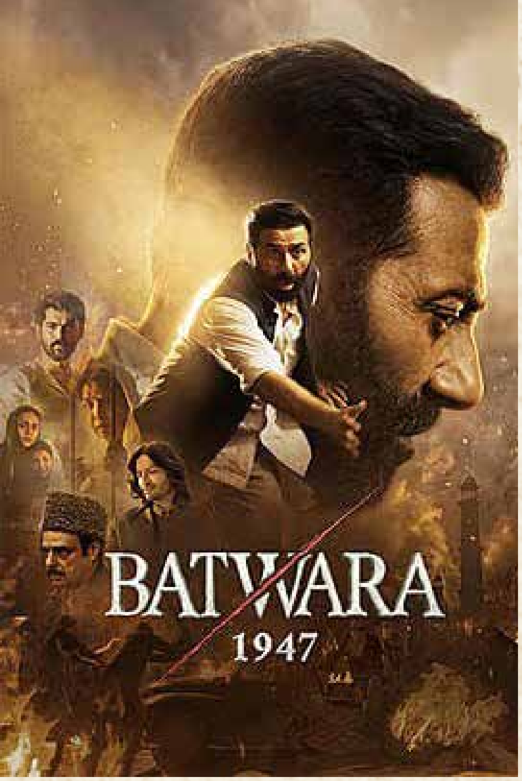

फिल्म समीक्षा

बंटवारा 1947
फिल्म या नैरेटिव का खेल

'बंटवारा -1947' देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी (मुम्बईया) फिल्म है। फिल्म देखकर समझ नहीं आता कि ये फिल्म हिंदुस्तान में बनी है या पाकिस्तान में। पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बनी तो हिंदुस्तान में है, लेकिन बनाने वाले पाकिस्तानी सोच के हैं। बरसों से सिनेमा के माध्यम से एक नैरेटिव देश में स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहा है कि एक विशेष कौम शांतिप्रिय है। देश की तमाम समस्याओं की जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज पर है और जबसे देश में 2014 के बाद प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गया है। ये फिल्म इससे एक कदम ओर आगे बढ़ गई है। अभी तक तो इस तरह की कहानी देश में ही सेट की जाती थी लेकिन 'बंटवारा 1947' की कहानी पाकिस्तान में सेट की गई है।

कहानी है दंगो में मेरठ से अपनी जान बचा कर किसी तरह सिकंदर मिर्ज़ा (सनी देओल) लाहौर पहुंचा है। कुछ दिन बाद उसको वहां से भागे एक हिंदू परिवार का घर भी रहने को मिल जाता है। सब ठीक है, लेकिन बस एक परेशानी है। वहां एक बूढ़ी औरत है, जो घर छोड़ कर भागे हुए हिंदू परिवार की सदस्य है। वो वहां अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही है, उसको विश्वास है कि उसका बेटा उसको लेने के लिए वापिस आएगा। शुरुआत में थोड़ी अनबन हुई फिर परिवार का उसको स्वीकार कर लेना। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन सियासत और मजहब के ठेकेदार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर क्या अच्छे और बुरे शांतिदूतों के बीच मित्रतापूर्ण जंग। बुराई पर अच्छाई की जीत, सब ठीक हो जाना और अंत में हिंदू औरत की मृत्यु के बाद वहां के मुस्लिम समुदाय का उसको अंतिम विदाई देना। ऊपर से देखें तो लगता है कि बड़ी आदर्शवादी कहानी है, लेकिन अगर थोड़ा चिंतन करें तो पता चलता है कि किस तरह से एक विशेष किस्म के नैरेटिव को सेट किया गया है।

'बंटवारा 1947' जनाब असग़र वज़ाहत साहेब के 1989 में लिखे नाटक 'जिस लाहौर नहीं देख्या ओ जम्याई नई' अर्थात् जिसने लाहौर नहीं देखा वह पैदा ही नहीं हुआ, पर आधारित है। ये नाटक अपने समय में काफी लोकप्रिय हुआ था। ये एक स्थापित सत्य है कि सिनेमा, रंगमंच, शिक्षा, कला, संस्कृति के क्षेत्र में वाम विचारधारा का प्रभुत्व रहा है। देश की स्वतंत्रता के बाद से ही रशियन एजेंसी केजीबी और अमेरिका की एजेंसी सीआईए ने भारतीय जनमानस को प्रभावित करने के लिए कई तरह से प्रयास किए थे। केजीबी के एजेंट मित्रोखिन ने अपने एक डॉक्यूमेंट को पब्लिक करके हिंदुस्तान में किस तरह से अपने एजेंट सेट किए थे उसके बारे में बताया है। मित्रोखिन आर्काइव के नाम से ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने लिखा है कि जो भी लोग सोसाइटी में मैटर करते थे उनको वो अपने काम के लिए प्रयोग करते थे। हिंदुस्तान में भी उन्होंने यही किया था। राजनेता, कवि,शायर, रंगमंच के कलाकार, लेखक, फिल्म अभिनेता, शिक्षक, प्रोफेसर आदि एक लम्बी सूची थी। इस काम में प्रयोग होने वाले लोगों की। ऐसे लोगों को ये यूजफुल इडियट्स कहते थे। असग़र वजाहत साहेब भी वाम

'बंटवारा 1947' विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है, जिसमें एक विशेष नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जिसे दर्शकों ने इसे एक सिरे से नकार दिया है।

अतुल गंगवार

विचारधारा से प्रभावित लेखक हैं। कहीं ना कहीं उनके लेखन पर विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। बड़ी सफाई से उन्होंने मुसलमान बनाम मुसलमान करके नाटक को प्रभावी बनाने का काम किया है। बात अपनी कह भी दी और कुछ कहा भी नहीं।

इस नाटक को फिल्मकार राज कुमार संतोषी ने सिनेमा के पर्दे पर उतारा है। इसमें उन्हें साथ मिला है आमिर खान का जो इसके निर्माता हैं। हमारे गदर नायक सनी देओल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है और उनका साथ दिया है प्रीति जिंटा ने, जो लम्बे समय के बाद पर्दे पर दिखी हैं। साथ में हैं करण देओल, अली फ़ज़ल, अभिमन्यु सिंह, ख़ुशी हजारे और शबाना आज़मी। इस फिल्म को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य जो भी हो लेकिन दर्शकों ने इसको सिरे से नकार दिया है। लम्बा समय लगा है, लेकिन आज का दर्शक सिनेमा की आड़ में खेले जा रहे इस खेल को समझ चुका है।

मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इस फिल्म का निर्माण किया है और एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। 'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल ने 'गदर 2', 'जाट' और 'बॉर्डर 2' की सफलता से बॉक्स ऑफिस को हिलाया हुआ था, लेकिन उनकी प्रचलित छवि से अलग रोल में उनको दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। देशभक्त सनी देओल की इमेज का कचरा कर दिया गया है। राजकुमार संतोषी का निर्देशन थका हुआ है। फिल्म की एकमात्र हाईलाइट शबाना आज़मी हैं। उन्होंने अपने किरदार को बढ़िया निभाया है। सनी देओल की बेटी के रोल में खुशी हजारे भी जमी हैं। ए. आर. रहमान का संगीत, जावेद अख़्तर के गीत हैं। फिल्म देखकर लगता है कि आमिर खान ने फिल्म पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनका ब्रांड बच गया, लेकिन अगर पैसों के नुकसान की बात करें तो आमिर खान की फ्लॉप फिल्में चीन में पैसा कमा ही लेती हैं. कैसे? शोध का विषय है।

सच तो ये है अब दर्शक पहले से अधिक जागरूक हो गया है। वो कहानी के अंदर की कहानी समझ लेता है। शायद यही कारण है भारतीय विचार, देशभक्ति, संस्कृति और आस्था से जुड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। 'धुरंधर' के दोनों भागों की अभूतपूर्व सफलता ने ये सिद्ध किया है कि देश क्या देखना चाहता है। अभी हाल ही में प्रदर्शित हुई फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता भी लोगों को आश्चर्य चकित कर रही है। अभी तक 2 करोड़ (लागत स्पष्ट नहीं) के बजट में बनी ये फिल्म 40 करोड़ से अधिक कमा चुकी है और ये कमाई अभी चल रही है। ■■■

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For A Better World
मासिक पत्रिका

शुल्क ₹ 500

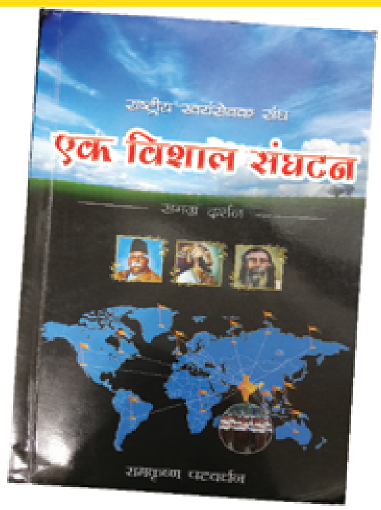

रा. स्व. संघ की स्थापना से लेकर शतकपूर्ति की यात्रा के विभिन्न पड़ावों तथा भविष्य के उद्देश्यों का सम्पूर्ण संकलन व आंकलन करने वाली पुस्तक

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ऑनलाईन पंजीयन करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA-HINDI VIVEK

Bank : Bank of Maharashtra **Branch :** Prabhadevi
A/C No. : 60085108000 **IFSC :** MAHB0000318

सम्पर्क - 9594991884 Email : hindivivekvargani@gmail.com

आईवीएफ से जन्मी लखीमी बछिया

असम ने पशुधन जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। राज्य की देसी लखीमी नस्ल की दुनिया की पहली आईवीएफ (इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन) बछिया का जन्म हुआ है। यह सफलता गुवाहाटी के खानापारा स्थित असम वेटरिनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी की आईवीएफ लैब में मिली।

मुख्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असम के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए वैज्ञानिकों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सभ्यता, संस्कृति और सृजन का सुंदर संगम है और इससे राज्य के पशुधन व डेयरी क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी-विशेषकर देसी नस्लों के संरक्षण, रोग नियंत्रण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में।

16 साल की आयु में बना चार्टर्ड अकाउंटेंट

भारतीय मूल के लक्ष्मणन मेय्यप्पन ने महज 16 साल की आयु में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट बन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। लक्ष्मणन ने 15 साल की आयु में एसीसीए की पढ़ाई शुरू की और लगभग एक साल में क्वालिफिकेशन पूरी कर ली। इसके बाद उन्होंने सीएफए चार्टर भी प्राप्त किया और फिलहाल फाईनेंस में एमएससी की पढ़ाई के साथ दुबई में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं।

स्केट मछली की नई प्रजाति की खोज

भारत के समुद्री जैव-विविधता अध्ययन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के वैज्ञानिकों ने आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से अरब सागर में गहरे समुद्र में पाई जाने वाली स्केट मछली की एक नई प्रजाति की खोज और पहचान की है। केरल तट के पास इसकी खोज हुई।

जेडएसआई द्वारा मंगलवार को जारी बयान के अनुसार नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम डिप्टुरस धृतिया रखा गया है, जिसे सामान्य रूप से अरबियन स्केट कहा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह खोज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के महत्वाकांक्षी गहरे महासागर मिशन के तहत चल रहे भारत के गहरे 'समुद्री कॉन्ड्रिक्थियंस : वर्गीकरण, वितरण, जीव विज्ञान और वर्तमान स्थिति' परियोजना के अंतर्गत किए गए समुद्री सर्वेक्षण के दौरान हुई।

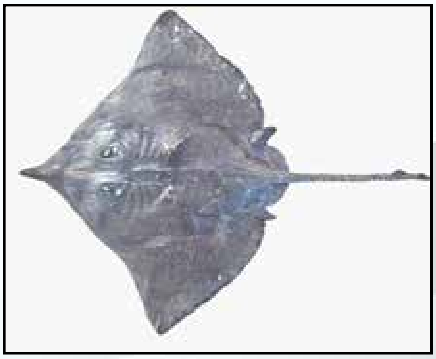

टैटू और नाक-कान छिदवाना कितना घातक

मेले में नाक-कान छिदवाना और टैटू बनवाना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कई बार एक ही सुई का प्रयोग कई लोगों पर करते हैं। ऐसे में सुई या उपकरण किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के खून से दूषित हों और उन्हें बिना ठीक से स्टरलाइज किए दोबारा प्रयोग किया जाए, तो एचआईवी एड्स का खतरा हो सकता है। विदित हो कि पैसों की बचत और जागरूकता की कमी के कारण टैटू कलाकार एक ही सुई का प्रयोग कई लोगों पर कर देते हैं। यदि सुई किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में चुभी है, तो वही सुई बिना स्टरलाइज़ किए दूसरे व्यक्ति में प्रयोग होते ही वायरस को सीधे खून में पहुंचा देती है। ग्रामीण क्षेत्रों और बाजारों में बिना सुरक्षा मानकों के एक ही औजार से नाक और कान छिदवाने से भी संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया है।

अमेठी में तैयार हुआ शेर

अमेठी के कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में भारत की पहली 100% स्वदेशी ए.के. 203 असॉल्ट राइफल तैयार हो चुकी है, जिसे सैनिकों द्वारा 'शेर' नाम दिया गया है। आईआरआपीएल द्वारा बनाई गई इस राइफल ने ऑटोमैटिक और बर्स्ट फायरिंग ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। स्वदेशी सामग्री: अब तक जो राइफलें बन रही थीं, उनमें कुछ रूसी पुर्जे प्रयोग हो रहे थे। लेकिन 'शेर' के सभी 50 मुख्य कंपोनेंट्स और 180 सब-पार्ट्स पूरी तरह से भारतीय उद्योगों द्वारा तैयार किए गए हैं। वजन और डिजाइन: इसका वजन करीब 3.8 किलोग्राम है। अमेठी की इस फैक्ट्री को इस तरह अपग्रेड किया जा रहा है कि यहाँ हर 100 सेकंड में एक 'शेर' राइफल बनकर तैयार होगी। 2030 तक इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना के लिए कुल 6 लाख से अधिक राइफलों का निर्माण किया जाना है।

समाचार

किशोर शितोले को मिला मराठवाड़ा भूषण पुरस्कार

छत्रपति सम्भाजीनगर। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ, मुम्बई की ओर से सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने सहकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए किशोर शितोले को मराठवाड़ा भूषण पुरस्कार प्रदान किया। बहुजन विकास मंत्री अतुल सावे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ज्योति शितोले को भी उक्त सम्मान से सम्मानित किया गया।

आइकन स्टील के डायरेक्टर उष्मेश राठी को मॉरिशस में आयोजित 'लोकमत वन वर्ल्ड समिट' में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' और युवा उद्यमी के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखूल, लोकमत ग्रुप के चेयरमैन डॉ. विजय दर्डा, पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह समेत कई प्रतिष्ठित हस्तियों को साथ मंच साझा किया।

टीजेएसबी सहकारी बँक लिमिटेड. मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank
उद्योजकांना खेळते भांडवल मिळवण्यासाठी
टीजेएसबी बँक गोल्ड ओव्हरड्राफ्ट कर्ज – एक स्मार्ट निवड.
मुख्य वैशिष्ट्ये
₹25 लाखांपर्यंत कर्ज
कमीत कमी कागदपत्रे
निधीची त्वरित उपलब्धता
शून्य पूर्वपरतफेड शुल्क
व्यवसाय विस्तारासाठी
सुलभ परतफेडीचा पर्याय
आकर्षक व्याजदर
TJSB SAHAKARI BANK LTD.
Or Bearer
या धारक को
Rupees रुपये One Lakh Only
₹ 1,00,000/-
अटी लागू*
www.tjsb.bank.in | ✆ : 022-48897208